को 165.46 लाख रुपये की लागत पर योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। इससे पहले वाम तट पर प्रतिप्रवाह भागों में पंचनाना नाले तक वर्तमान तटबन्ध को ऊंचा करने और सुदृढ़ करने के साथ-साथ तटबन्ध का निर्माण करने के लिए 313.28 लाख रुपये की पटना सुरक्षा निर्माण-कार्यों के साथ योजना आयोग द्वारा एक अन्य स्कीम जून, 1980 में स्वीकृत की जा चुकी थी।

गया और पटना जिलों के क्षेत्रों के लाभ के लिए पुनपुन-दरधा सिंचाई स्कीम को अलग से तैयार किया गया है जिसपर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों पर राज्य सरकार के स्पष्टीकरणों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

बाढ़ नियन्त्रण के लिए बिहार की योजनाएं

1306. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए कुछ योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उक्त कितनी योजनाओं को स्वीकृति दी है; और

(घ) उनके कार्यान्वयन के लिए सिंचाई मन्त्रालय द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी ;

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) बिहार सरकार ने बहुत सी स्कीमें तैयार की हैं तथा ये स्कीमें स्वीकृति एवं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। स्कीमों का कार्यान्वियन राज्यों के वार्षिक बजट में निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक योजना दस्तावेज के अनुसार छठी योजना से पहले चल रहीं 21 स्कीमें क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। राज्य सरकार ने छठी योजना के दौरान शुरू की गई या शुरू करने के लिए विचार की गई 41 स्कीमों की भी सूची तैयार की है तथा सम्पूर्ण राज्य में जल-निकास, शहर की सुरक्षा तथा कटावरोधी कार्यों के लिए एकमुश्त प्रावधान किया है।

(ग) योजना आयोग ने कलैण्डर वर्ष 1982 तथा 1983 के दौरान 76.73 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के बाद नियंत्रण घटक सहित 6 स्कीमों को स्वीकार्य पाया है।

(घ) बाढ़ नियन्त्रण स्कीमों का कार्यान्वयन राज्य सरकार अपने वार्षिक योजना बजट में से करती है।

सिंचाई योजनाओं के लिए बिहार का प्रस्ताव

1307. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार द्वारा सिंचाई योजनाओं की एक सूची केन्द्रीय मन्त्रालय को प्रस्तुत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं की क्रियान्विति पर कितनी व्यय होने का अनुमान है;

(घ) क्या राज्य सरकार द्वारा इन योजनाओं की कार्यान्वयान के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी धनराशि क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ङ) बिहार सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्राथमिकता के आधार पर राज्य द्वारा पूरा किए जाने के लिए प्रस्तावित 35 चालू वृहत् तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का निर्धारण किया है तथा उनकी सूची भेजी है। इन स्कीमों के नाम, उनकी अनुमानित लागत, संचयी व्यय, इन परियोजनाओं से सिंचाई लाभ आदि विवरण में दिए गए हैं। जो सभा पटल पर रखा गया। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या LT. -7872/84] राज्य सरकार ने इन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए किसी विशेष वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध नहीं किया है। तथापि, सिंचाई एक राज्य विषय होने के कारण इन परियोजनाओं की वित्त-व्यवस्था उनके अपने बजट के अन्तर्गत की जाती है। केन्द्र, राज्यों को ब्लाक ऋण तथा अनुदान देता है जो विकास के किसी सेक्टर या परियोजना से जुड़े हुए नहीं होते। राज्य द्वारा 1984-85 के लिए अलग-अलग स्कीम के लिए आवश्यक निधियों की मांगों पर योजना आयोग के एक कार्यकारी दल द्वारा पुनरीक्षा की गई थी तथा विवरण में शामिल इन अभिज्ञात परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग ने आवश्यक आबंटन कर दिये हैं।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) का कार्यान्वयन

1308. **श्री रामावतार शास्त्री**: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित 14 मुद्दों को

"क" "ख" और "ग" तीनों श्रेणियों के राज्यों में द्विभाषी रूप में क्रियान्वित करने का प्रावधान है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान "क" "ख" और "ग" श्रेणियों के राज्यों में स्थित उनके मंत्रालयों, विभागों, सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों तथा उपक्रमों द्वारा धारा 3 (3) के कार्यान्वयन की प्रतिशतता का राज्यवार तथा वर्ष वार का पृथक रूप से ब्यौरा क्या है;

(ग) तीनों श्रेणियों के राज्यों में उपर्युक्त सभी 14 मुद्दों के कार्य को शत प्रतिशत द्विभाषी करने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है?

सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) जी, हां।

(ख) सिचाई मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) के कार्यान्वयन के संबंध में ब्यौरा संलग्न उपाबन्ध में दिया गया है। "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों के राज्यों में स्थित सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा उपक्रमों के संबंध में ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) और (घ) राजभाषा अधिनियम, 1963 में उल्लिखित कागजात से संबंधित धारा 3(3) के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस उपाय की आवश्यकता पर विभिन्न सरकारी बैठकों तथा हिन्दी सलाहकार समिति आदि की बैठकों के दौरान भी जोर डाला जाता है।

विवरण

क्रम सं०	कागजात	1981-82				1982-83				1983-84			
		द्विभाषिक	अंग्रेजी	कुल	%	द्विभाषिक	अंग्रेजी	कुल	%	द्विभाषिक	अंग्रेजी	कुल	%
1.	संकल्प												
2.	अधिसूचना	205	1	205	100%	164	—	164	100%	176	—	176	100%
3.	नियम												
4.	प्रशा० रिपोर्ट	1	—	1	100%	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	प्रेस विज्ञप्तियां	3	—	3	तदैव	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	संसद में प्रस्तुत किए गए कागजात	484	—	484	तदैव	847	—	847	100%	637	—	637	100%
7.	संविदाए	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	लाइसेन्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	परमिट	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	नोटिस	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	टेण्डर फार्म	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	अन्य रिपोर्टें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	करार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	सामान्य आदेश	1429	275	1704	84%	914	860	1774	52%	1023	1155	2178	47%

Additional Irrigation Projects Under Command Area

1309. SHRI G. Y. KRISHNAN : Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Union Government have decided to bring some more additional irrigation projects under the Command Area ; and

(b) if so, the details in this regard, State-wise, and targets fixed for the Sixth Five Year Plan ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) Yes Sir.

(b) The details of the new projects included under the Centrally sponsored CAD Programme are given below. No target in this regard has been fixed for the Sixth Five Year Plan.

State	*Name of Project*
Andhra Pradesh	1. Swarna Project
	2. Vamsadhara Stage-I Project
	3. Paddavagu Project
Maharashtra	1. Manjare Project
	2. Khadakwasla Project
	3. Upper Godavari Project
	4. Surya Project